

UGC NET Paper 1 2008 June

www.Fillerform.info

Previous Years Solved Questions - UGC NET Paper 1 for July 201

Unit 3(Home work)Hindi/Eng-23 with ans

Read the following passage and answer the questions 11 to 15:

The fundamental principle is that Article 14 forbids class legislation but permits reasonable classification for the purpose of legislation which classification must satisfy the twin tests of classification being founded on an intelligible differentia which distinguishes persons or things that are grouped together from those that are left out of the group and that differentia must have a rational nexus to the object sought to be achieved by the Statute in question. The thrust of Article 14 is that the citizen is entitled to equality before law and equal protection of laws. In the very nature of things the society being composed of unequals a welfare State will have to strive by both executive and legislative action to help the less fortunate in society to ameliorate their condition so that the social and economic inequality in the society may be bridged. This would necessitate a legislative application to a group of citizens otherwise unequal and amelioration of whose lot is the object of state affirmative action. In the absence of the doctrine of classification such legislation is likely to flounder on the bed rock of equality enshrined in Article 14. The Court realistically appraising the social and economic inequality and keeping in view the guidelines on which the State action must move as constitutionally laid down in Part IV of the Constitution evolved the doctrine of classification. The doctrine was evolved to sustain a legislation or State action designed to help weaker sections of the society or some such segments of the society in need of succour. Legislative and executive action may accordingly be sustained if it satisfies the twin tests of reasonable classification and the rational principle correlated to the object sought to be achieved.

The concept of equality before the law does not involve the idea of absolute equality among human beings which is a physical impossibility. All that Article 14 guarantees is a similarity of treatment contra-distinguished from identical treatment. Equality before law means that among equals the law should be equal and should be equally administered and that the likes should be treated alike. Equality before the law does not mean that things which are different shall be as though they are the same. It of course means denial of any special privilege by reason of birth, creed or the like. The legislation as well as the executive government, while dealing with diverse problems arising out of an infinite variety of human relations must of necessity have the power of making special laws, to attain any particular object and to achieve that object it

must have the power of selection or classification of persons and things upon which such laws are to operate.

11. Right to equality, one of the fundamental rights, is enunciated in the constitution under Part III, Article:

(A) 12

(B) 13

(C) 14

(D) 15

Answer: (C)

12. The main thrust of Right to equality is that it permits:

(A) class legislation

(B) equality before law and equal protection under the law

(C) absolute equality

(D) special privilege by reason of birth

Answer: (B)

13. The social and economic inequality in the society can be bridged by:

(A) executive and legislative action

(B) universal suffrage

(C) identical treatment

(D) none of the above

Answer: (A)

14. The doctrine of classification is evolved to:

- (A) Help weaker sections of the society
- (B) Provide absolute equality
- (C) Provide identical treatment
- (D) None of the above

Answer: (A)

15. While dealing with diverse problems arising out of an infinite variety of human relations, the government

- (A) must have the power of making special laws
- (B) must not have any power to make special laws
- (C) must have power to withdraw equal rights
- (D) none of the above

Answer: (A)

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और 11 से 15 प्रश्नों के उत्तर दें:

मूल सिद्धांत यह है कि अनुच्छेद 14 कक्षा कानून को निषिद्ध करता है, लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जो वर्गीकरण को बुद्धिमानी से अलग होने पर स्थापित किए जाने वाले वर्गीकरण के जुड़ाव परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जिन्हें उन लोगों से अलग किया जाता है जिन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है समूह और उस विभेदीकरण के पास एक तर्कसंगत तर्क होना चाहिए जो उस वस्तु को प्राप्त करना है जिसे विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किया जाना है। अनुच्छेद 14 का जोर यह है कि नागरिक कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है। समाज की असमानताओं से निर्मित होने वाली चीजों की बहुत ही प्रकृति में, कल्याणकारी राज्य को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए समाज में कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए कार्यकारी और विधायी कार्रवाई दोनों का प्रयास करना होगा ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को पाटा जा सके। इसके लिए नागरिकों के एक समूह के लिए एक

विधायी आवेदन की आवश्यकता होगी अन्यथा असमान और संशोधन जिनके राज्य की पुष्टि कार्रवाई की वस्तु है। वर्गीकरण के सिद्धांत की अनुपस्थिति में इस तरह के कानून के अनुच्छेद 14 में बराबरी की बिस्तर की चट्टान पर लहराता है। संविधान के भाग IV में वर्गीकरण का सिद्धांत विकसित हुआ। सिद्धांत समाज के कमजोर वर्गों या समाज के कुछ ऐसे वर्गों की मदद करने के लिए बनाए गए एक कानून या राज्य कार्रवाई को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया था। विधायी और कार्यकारी कार्रवाई तदनुसार हो सकती है यदि यह उचित वर्गीकरण के जुड़वां परीक्षणों को संतुष्ट करता है और प्राप्त करने के लिए आवश्यक वस्तु से संबंधित तर्कसंगत सिद्धांत।

कानून के समक्ष समानता की अवधारणा में मनुष्यों के बीच पूर्ण समानता का विचार शामिल नहीं है जो कि शारीरिक अक्षमता है। सभी कि अनुच्छेद 14 गारंटी उपचार उपचार की एक समानता है जो समान उपचार से अलग है। कानून से पहले समानता का मतलब है कि बराबरी के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए और पसंद को समान माना जाना चाहिए। कानून के समक्ष समानता का मतलब यह नहीं है कि जो चीजें अलग हैं वे वैसे ही होंगी जैसे वे एक ही हैं। यह निश्चित रूप से जन्म, पंथ या इस तरह के कारण से किसी विशेष विशेषाधिकार से इनकार करने का मतलब है। कानून के साथ-साथ कार्यकारी सरकार, विभिन्न प्रकार की मानवीय संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए, विशेष कानून बनाने, किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने और उस वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यक्तियों और चीजों का चयन या वर्गीकरण जिस पर ऐसे कानून संचालित होते हैं।

11. समानता का अधिकार, मौलिक अधिकारों में से एक, भाग III के तहत संविधान में वर्णित है, अनुच्छेद:

(ए) 12

(ब) १३

(ग) १४

(D) 15

उत्तर: (सी)

12. समानता का अधिकार का मुख्य जोर यह है कि यह अनुमति देता है:

(ए) वर्ग विधान

(ख) कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान सुरक्षा

(ग) पूर्ण समानता

(घ) जन्म के कारण विशेष विशेषाधिकार

उत्तर: (बी)

13. समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को इससे प्रभावित किया जा सकता है:

(ए) कार्यकारी और विधायी कार्यवाही

(बी) सार्वभौमिक मताधिकार

(सी) समान उपचार

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (ए)

14. वर्गीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित है:

(ए) समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना

(ख) पूर्ण समानता प्रदान करें

(सी) समान उपचार प्रदान करें

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (ए)

15. विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंधों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए, सरकार

(ए) के पास विशेष कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए

(बी) के पास विशेष कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए

(सी) के पास समान अधिकार वापस लेने की शक्ति होनी चाहिए

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (ए)